बाबा नागार्जुन की कविता

किसकी है जनवरी, किसकी अगस्त है ?
कौन यहां सुखी है, कौन यहां मस्त है ?
सेठ है, शोषक है, नामी गला-काटू है
गालियां भी सुनता है, भारी थूक-चाटू है
चोर है, डाकू है, झूठा-मक्कार है
कातिल है, छलिया है, लुच्चा-लबार है
जैसे भी टिकट मिला, जहां भी टिकट मिला
शासन के घोड़े पर वह भी सवार है
उसी की जनवरी छब्बीस
उसी का अगस्त है
बाकी सब दुखी है, बाकी सब पस्त है
कौन है खिला-खिला, बुझा-बुझा कौन है कौन है बुलंद
खिला-खिला सेठ है, श्रमिक है बुझा बुझा
मालिक बुलंद है, कुली-मजूर पस्त है
सेठ यहां सुखी है, सेठ यहां मस्त है
उसकी है जनवरी, उसीका अगस्त है
पटना है, दिल्ली है, वहीं सब जुगाड़ है
मेला है, ठेला है, भारी भीड़-भाड़ है
फ्रीज है, सोफ़ा है, बिजली का झाड़ है
फैशन की ओट है, सब कुछ उघाड़ है
पब्लिक की पीठ पर बजट का पहाड़ है
गिन लो जी, गिन लो, गिन लो, जी गिन लो,
मास्टर की छाती में कै ठो हाड़ है!
गिन लो जी, गिन लो, गिन लो जी, गिन लो,
मज़दूर की छाती में कै ठो हाड़ है!
गिन लो जी, गिन लो, गिन लो जी, गिन लो,
घरनी की छाती में कै ठो हाड़ है!
गिन लो जी, गिन लो, गिन लो जी, गिन लो,
बच्चे की छाती में कै ठो हाड़ है!
देख लो जी, देख लो, देख लो जी, देख लो,
पब्लिक की पीठ पर बजट का पहाड़ है!
मेला है, ठेला है, भारी भीड़-भाड़ है
पटना है, दिल्ली है, वहीं सब जुगाड़ है
फ्रिज है, सोफ़ा है, बिजली का झाड़ है,
फैशन की ओट है, सब कुछ उघाड़ है
महल आबाद है, झोपड़ी उजाड़ है
गरीबों की बस्ती में उखाड़ है, पछाड़ है
धतू तेरी, धतू तेरी, कुच्छो नहीं ! कुच्छो नहीं
ताड़ का तिल है, तिल का ताड़ है
ताड़ के पत्ते हैं, पत्तों के पंखे हैं
पंखों की आट है, पंखों की आड़ है
कुच्छो नहीं, कुच्छो नहीं,
ताड़ का तिल है, तिल का ताड़ है,
पब्लिक की पीठ पर बजट का पहाड़ है
किसकी है जनवरी, किसका अगस्त है
कौन यहां सुखी है, कौन यहां पस्त है
सेठ ही सुखी है, सेठ ही मस्त है
मंत्री ही सुखी है, मंत्री ही मस्त है,
उसी की है जनवरी, उसी का अगस्त है,

ईएसआइ मेडिकल कॉलेज की दिशा.....

पेज एक का शेष

नियुक्तियां आज तक नहीं की गयी हैं, जिसके चलते 145 स्टाफ़ नर्स व 270 पैरामेडिकल स्टाफ़ के पद खाली पड़े हैं। इन खाली पदों पर अर्ध शिक्षित काम चलाऊ थोड़े से स्टाफ़ को ठेके पर रख कर जैसे-तैसे काम को घसीटा जा रहा है।

क्लर्क के 110 पदों के लिये मई 2016 में परीक्षा ली गयी थी, लेकिन आज तक भी नियुक्तियां न होने की वजह से मात्र 13 बाबुओं से काम चलाने का तमाशा हो रहा है। इन पदों पर ठेके पर भी नहीं रख सकते।

उपकरणों की तो ना ही पूछो। आज तक भी इतने बड़े इस अस्पताल में 33 साल पुरानी एक्सरे मशीन से मरीज़ों को बहलाया जा रहा है। अल्ट्रासाऊंड व अन्य उपकरणों की स्थिति भी अच्छी नहीं है।

कॉलेज के डीन को मात्र 25 लाख रुपये तक के सामान खरीदने की इजाजत है। इससे बड़ी कीमत के सामान खरीदने की पावर मुख्यालय में बैठे हरामखोर अफ़सरों ने अपने पास रखी है जो खरीद सम्बन्धी फ़ाइलों पर कुंडली मार कर बैठे रहते हैं। और तो और ओटी (ऑप्रेशन थियेटर) की टेबलों तक की फ़इलें बरसों से दबी पड़ी हैं। नई बिल्डिंग में 8 बड़े ओटी चल सकते हैं, जिसकी कि सख्त जरूरत है, लेकिन पुरानी बिल्डिंग के घिसे पिटे ओटी में ही बेगार काटी जा रही है।

ओटी के अभाव में मरीज़ों को बेज़ा इन्तज़ार कराया जाता है अथवा निजी व्यवसाइक अस्पतालों को रेफ़र कर दिया जाता है जिस पर निगम का करोड़ों रुपया खर्च होता है और मरीज़ अलग से दुखी होते हैं।

अल्ट्रासाऊंड की मात्र 2 छोटी मशीने खरीदी गयी हैं जो कि अपर्याप्त हैं। एक महंगी मशीन जिसकी जरूरत विशेष प्रकार

की जांचों के लिये होती है कि फ़ाइल मुख्यालय बरसों से अटकाये बैठा है। सीटी स्कैन जैसी मशीन जो आज बहुत आम हो चुकी है उसको खरीदकर लगाने की बजाय मुख्यालय के मूर्ख अधिकारी पीपीपी (पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप) मोड में लगवाने का प्रयास गत कई बरसों से कर रहे हैं।

दुनिया जानती है कि इस मोड में पूंजी लगाने वाला सबसे पहले अपना मोटा मुनाफ़ा सुनिश्चत करता है। यहां ऐसी कोई संभावना न देखते हुए कोई भी यहां पूंजी लगाने को तैयार नहीं फ़िर भी मुर्खालय के हरामखोर अधिकारी मशीन खरीदने की बजाय मरीज़ों को निजी अस्पतालों में भेजने पर तुले दिखते हैं। इनके अलावा अनेकों और भी उपकरण हैं जिनकी फ़ाइलें मूर्खालय अटकाये बैठा है।

मज़े की बात यह है कि इस सारे प्रोजेक्ट पर भारत सरकार का और न ही हरियाणा सरकार का कोई पैसा लगना है। इसका सारा पैसा मज़दूरों के वेतन से वसूला जाता है, और तो और चपरासी से लेकर डीजी तक का वेतन भी मज़दूरों की कमाई से निकलता है सुधि पाठक जानते हैं कि 21 हज़ार तक वेतन पाने वाले मज़दूरों से भारत सरकार का यह उपक्रम साढे 6 प्रतिशत मासिक झपट लेता है। इस रकम को मज़दूरों पर खर्च न करने के चलते ईएसआई निगम के पास आज 70 हज़ार करोड़ रुपया बतौर मुनाफ़ा जमा हुआ पड़ा है।

लौटते हैं मौलिक सवाल पर कि 'बेचारा' एक मंत्री अकेला क्या कर सकता है ? नेतृत्व तो एक अकेला ही करता है यदि सैंकड़ों-हज़ारों करने लगेंगे तो सब गुड़ गोबर हो जायेगा।

यदि उसकी नीयत साफ़ हो और पाखंड की अपेक्षा कुछ ठोस करने का इरादा हो तो अपनी नाक के नीचे पल रहे तमाम हरामखोरों को पलक झपकते ही ठिकाने लगा सकता है जिससे देश भर में काम सुचारू रूप से चल सकता है। फ़िर इन बंडारूओं को नकली आशीर्वाद की नौटंकी करने की जरूरत नहीं रह जायेगी।

जेल भ्रष्टाचार का बड़ा अड्डा.....

पेज एक का शेष

सर्दियों में जो गाजर मंडी में 5 से 10 रुपये किलो थी। जेल में 40 से 50 रुपये किलो थी। जो केला बाजार में 40 से 50 रुपये दर्जन है वहीं जेल में 80 से 90 रुपये है। प्याज, टमाटर हरी मिर्च आदि ही चीज़ का यही हाल है। फुल क्रीम वीटा का जो दूध बाज़ार में 26 रुपये प्रति थैली है जेल में 30 रुपये है। अक्तूबर में जब यह संवाददाता जेल पहुंचा तो वहां बीड़ी-सिगरेट बिल्कुल बंद थी इसका लाभ उठाकर कुछ वार्डर ड्यूटी पर आते समय 2-4 बंडल बीड़ी के ले आते थे और 10-15 रुपये का बंडल एक हज़ार से ढाई हज़ार तक में बिकता था। जेल में बीड़ी का भाव रोज़ाना शेयर मार्केट की तरह 50 रुपये से लेकर 100 रुपये प्रति बीड़ी तक चलता था। अप्रैल 2017 में बीड़ी खुली तो जेल प्रशासन ने अपनी कैंटीन के द्वारा 10 रुपये वाला बंडल 30 रुपये का बेचा।

मई में आये नये सुपरिंटेंडेंट अनिल कुमार ने कैदियों की नब्ज़ पकड़ते हुए पहले तो बीड़ी को बिल्कुल बन्द किया फ़िर उसी कैंटीन से 200 रुपये प्रति बंडल बिकवाया, इसे इन दामों में लेने के लिये भी कैदी ऐसे टूट कर पड़ते हैं जैसे कोई चीज़ मुफ्त मिल रही है। अपनी मार्केट बनाये रखने के लिये अनिल कुमार बीड़ी की बिक्री रोज़ाना न करके साप्ताहिक करता है।

जब कभी अनिल साहब किसी बात पर नाराज़ हो जाता है तो कैंटीन को बिल्कुल बन्द कर दिया जाता है। दूध, दही, पनीर आदि की आपूर्ति तक बिल्कुल बन्द कर दी जाती है। फ़िर उसके कुछ चमचों द्वारा मिन्नत खुशामद का नाटक करा कर धीरे-धरे सप्लाई शुरू की जाती है।

जब कभी सैशन जज, हाई कोर्ट जज या अन्य किसी वीआईपी को जेल भ्रमण पर आना होता है तो भी कैन्टीन बिन्कुल खाली करा दी जाती है। केवल वहीं चीजें कैन्टीन में उपलब्ध रहती हैं जो कम्प्यूटराइज़्ड है और बायोमीट्रिक (अंगूठा) सिस्टम से बेची जाती हैं। इनमें साबुन, टूथ पेस्ट, तेल, बिस्कुट शीतल पेय आदि होते हैं।

पहले लोग जब अपने भाई-बंधुओं को मिलने जेल में आते थे तो घर से खाना, घी, दूध, फ़ल व सब्ज़ियां आदि ले आया करते थे। कैन्टीन की बिक्री द्वारा अपनी लूट कमाई बढाने के लिये अब मुलाकाती कोई भी खाने-पीने की चाज़ नहीं ला सकता।

यह सब 'सुरक्षा' के नाम पर किया जा रहा है। इसके लिये जेल प्रशासन हाईकोर्ट के एक जज के आदेश का भी सहारा लेता है। लेकिन इस सबके बावजूद जेल में मोबाइल फ़ोन व सुल्फ़े की बिक्री खूब चल रही है। जेल में 5 से 6 किलो ग्राम सुल्फ़े की खपत प्रति माह होती है। इसकी आपूर्ति जेल कर्मचारियों द्वारा थोक विक्रेता कैदियों को की जाती है जो आगे परचून में बिक्री करने वाले कैदियों को बेचते रहते हैं। इसी तरह मोबाइल फ़ोन भी जेल में चलते हैं।

सवाल यह है कि जब जेल के उच्चाधिकारी रोज़ाना लाखों के वारे-न्यारे कर रहें हों तो छोटे कर्मचारी कैसे ईमानदार रह सकते हैं ? वे भी अपनी क्षमता एवं स्थिति के अनुसार हाथ मारते रहते हैं। जब कोई वार्डर किसी कैदी के पास मोबाइल या सुल्फ़ा पकड़ लेता है तो वह वहीं मौके पर हज़ार-दो हज़ार लेकर मामला निपटा देते है। यदि वह चक्कर यानी कंट्रोल रूम पर उसे लेकर जाता है तो वार्डर के पल्ले तो कुछ पड़ता नहीं, हां चक्कर वाले 10-20 हजार में जरूर मामला निपटा लेते हैं। और यही मामला यदि ड्योढी (बड़े दफ़्तरों) में पहुंच गया तो मामला लाखों में निपटता है, परन्तु नीचे वालों को धेला भी नहीं मिलता।

जेल में गिनती कटवाना यानी एक बैरक से अपनी पसंद की दूसरी बैरक में जाने का भी धंधा अच्छा-खासा है। वैसे गिनती का काम तो डिप्टी सुपरिंटेंडेंट द्वारा ही किया जाता है, परन्तु वहां तक पहुंचने की फ़ीस 3 से 10 हज़ार तक कुछ भी हो सकती है। यह काम मुंशियों व अर्दलियों का काम कर रहे कैदियों द्वारा खुले आम किया जाता है। इन सबके अलावा और बहुत से काले धंधे जेल में प्रशासन की मर्जी एवं मिलीभगत से चलाये जा रहे हैं।

मौजूदा व्यवस्था में जेल के भ्रष्टाचार को पकड़ पाना असम्भव सा है। इस भ्रष्टाचार के विरुद्ध जब कोई शिकायत करने की हिम्मत करता है तो उसको बहुत बुरी तरह से प्रताड़ित किया जाता है। जांच का ड्रामा करने जो विभाग का अधिकारी आता है उसके सामने जेल प्रशासन अपने हक में शिकायतकर्ता के विरुद्ध अपने चमचों से बयान दिलवाने के साथ-साथ जांच अधिकारी की अच्छी खासी 'सेवा' भी कर देता है।

जेल में कोई भी छापामार टीम तब तक प्रवेश ही नहीं कर सकती जब तक जेल प्रशासन न चाहे। इस लिये जेल के भ्रष्टाचार को पकड़ पाना आसान नहीं।

जेल में अखबार पढना भी बहुत महंगा पड़ता है। अखबार चाहे हिन्दी का हो या अंग्रेजी का, सभी के लिये 200 रुपया मासिक अग्रिम वसूल लेते हैं। इसके बावजूद अखबार 10 बजे मिलेगा या 11 बजे, या मिलेगा भी कि नहीं कोई ठिकाना नहीं। अखबार बांटने से पहले प्रशासन अपनी मर्जी से कुछ खबरों की कतरने भी काट लेता है।

नाई की दुकान का ठेका सुपरिंटेंडेंट की जेब में जाता है। यह 50 से 60 हज़ार मासिक होता है। इस दुकान को कैदी ही चलाते हैं जो आगे कैदियों से सेविंग के 50 व कटिंग के 100 रुपया तथा बाल रंगने आदि के अनाप शनाप वसूलते हैं। इसी तरह टेलर मास्टर व कपड़े प्रेस करने वाले भी बैठा रखें हैं। ड्योढी से जब कैदी पाजामा अन्दर लाते हैं तो सुरक्षा के नाम पर नाड़ा निकाल लिया जाता है। वही नाड़ा बनाने के टेलर मास्टर 50 रुपया वसूलता है। यानी कैदी द्वारा ही कैदी को लुटवा रहा है जेल प्रशासन अपनी जेब भरने के लिये।

इतनी खुली लूट अकेला जेलर या उसका प्रशासन तो नहीं ही कर सकता। इस लूट का हिस्सा ऊपर तक पहुंचे बिना यह लूट संभव नहीं हैं।

घर बैठे प्राप्त करें मज़दूर मोर्चा

आज ही अपने हॉकर से कहें कोई दिक्कत हो तो शर्मा न्यूज एजेंसी से फोन नं 9811159238 पर बात करें। बल्लभगढ के पाठक अरोडा न्यूज एजेंसी से 9811477204 पर बात करें:

अन्य बिक्री केन्द्र :

1. **आनंद मैगजीन सैंटर केसी रोड, एनएच-5,**
2. **प्रिंट फोर्ट टेलीफोन एक्सचेंज के सामने नेहरू ग्राउंड,**
3. **रेलवे बुक स्टाल ओल्ड रेलवे स्टेशन,**
4. **रैंक, 45 नीलम चौक,**
5. **एनआईटी रेलवे स्टेशन के बाहर बाटा चौक पुल के नीचे,**
6. **राम खिलावन बल्लभगढ़ बस अड्डा पुलिस चौकी के सामने,**
7. **हितेश ग्रोवर सैक्टर 29 पेट्रोल पम्प के पास ।**
8. **जितेन्द्र, बाटा सैंटर - 9971064207**
9. **स्थानीय अदालतों में : चैम्बर नं. 56-एस.के .जोशी - वकील साहब**